www.tamsasanket.com
वर्षः 05|| अंक 20||लखनऊ
वार
20 अप्रैल 2026|| पृष्ठः 04 ||मूल्यः ₹2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा

दैनिक तमसा संकेत

डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
https://epaper.tamsasanket.com
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

मौसम
सूर्योदयः 05:39
सूर्यास्तः 06:32
अधिकतमः 41°00
न्यूनतमः 26°00

पेज 03

विशेष समाचार
अतिक्रमण रोकने में सरकारों की... >> पेज 02
बैलेंस खत्म होने पर 3 दिन तक नहीं... >>पेज 04
तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग भारतीय फिल्म...

फास्ट न्यूज

पहलगाम हमले की बरसी से पहले कश्मीर में सुरक्षा बढ़ी

पहलगाम । पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी से पहले कश्मीर भर के टूरिस्ट स्पॉट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे पहलगाम हमले की बरसी पर टूरिस्ट स्पॉट्स के आस-पास, किसी भी संभावित आतंकी हमले को लेकर सतर्क रहें।

कार्यवाही तैयारी

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की तैयारी में विपक्ष

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्ष एक बार फिर कोशिश में जुटा है। सूत्रों के अनुसार, कई विपक्षी दलों के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। करीब पांच सीनियर लीडर एक नए नोटिस का मसौदा तैयार करने पर काम कर रहे हैं, ताकि हटाने की कार्यवाही शुरू की जा सके। इससे पहले मार्च में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद में नोटिस दिया था।

हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन नोटिसों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप उन्हें हटाने के लिए आवश्यक उच्च संवैधानिक मानदंडों को पूरा नहीं करते।

उज्जैन में मॉडल हर्षा रिछारिया ने लिया संन्यास

उज्जैन। सोशल मीडिया इन्फलुएंसर, कंटेंट क्रिएटर और मॉडल हर्षा रिछारिया ने रविवार को अक्षय तृतीया पर संन्यास ले लिया। उन्हें उज्जैन के मौनी तीर्थ आश्रम में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सुमनानंद गिरि महाराज ने संन्यास दीक्षा दी। संन्यास परंपरा के अनुसार, उन्हें शिखा और दंड त्याग की विधि कराई गई। साथ ही तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म भी कराए गए, जो पूर्व जीवन के त्याग और नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक माने जाते हैं।

पीएम मोदी ने लोगों संग चखा झालमुड़ी का स्वाद चुनावी रैली के बीच पीएम मोदी का 'बंगाली अंदाज'

टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ धोखा किया है : मोदी

दौरा

तमसा संकेत, एजेंसी

कोलकाता । पीएम मोदी रविवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। झाड़ग्राम में उन्होंने रैली की। इस दौरान रास्ते में वह एक दुकान पर रुके और झालमुड़ी खाई।

झालमुड़ी बनाते हुए दुकानदार ने पूछा कि आप प्याज खाते हैं। पीएम ने जवाब दिया- हां प्याज खाता हूं बस दिमाग नहीं। यह सुनकर दुकानदार हंसने लगा।

पीएम ने दुकानदार से इस मुलाकात का करीब 40 सेकेंड का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। पीएम जिस दुकान पर झालमुड़ी खाने गए थे। उस दुकानदार का नाम बिक्रम साव है, वह बिहार का रहने वाला है। अब अपने मां-पिता के साथ बंगाल में रहता है।

पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में एक नमकीन की दुकान पर गए। वहां उन्होंने झालमूड़ी खाई।

दुकानदार ने पूछा- प्याज खाते हैं, मोदी बोले- प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं

टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ धोखा किया है

पीएम बोले बंगाल की बहनें चाहती थीं कि उनको 33 प्रतिशत आरक्षण मिले। मोदी ने इसके लिए भी प्रयास किया। लेकिन टीएमसी नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में विधायक सांसद बनें। क्योंकि ये बेटियां इनके जंगलराज को चुनौती दे रही हैं।

>> (शेष पेज 04 पर)

पीएम मोदी ने टीएमसी पर जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने और भ्रष्टाचार और जबरन वसूली की व्यवस्था चलाने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि अगर घर बनाना हो तो टीएमसी के गठबंधन पर निर्भर रहना पड़ता है. टीएमसी के सांसदों और विधायकों को आपकी समस्याओं की कोई परवाह नहीं है. वो तो बस अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं

वर्धा और राजनांदगांव में 45 डिग्री तापमान

छत्तीसगढ़-ओडिशा-झारखंड में रात में लू का अलर्ट

अलर्ट

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर/ लखनऊ । देश के उत्तरी-पश्चिमी राज्यों और मध्य भारत में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और महाराष्ट्र के वर्धा में तापमान 45 C रिकॉर्ड हुआ।

शनिवार को देश के 10 सबसे गर्म शहरों में यूपी का बांदा 44.6, तेलंगाना का आदिलाबाद 44.3, महाराष्ट्र के नागपुर-अमरावती 44.2 और मध्य प्रदेश का रतलाम 44 C भी शामिल रहा। राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में तापमान 43 C से ज्यादा रहा। यानी मई से पहले ही तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी हो गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड में आज रात को भी लू चलने का अलर्ट जारी किया है।

यहां लगातार तीसरे दिन पारा 40डिग्री सेल्सियस से ज्यादा

>> (शेष पेज 04 पर)

आरोप : झोलाछाप डाक्टर दे रहा है परिवार को धमकी-'जो करना है कर लो'

कमर में इंजेक्शन पैर सुन्न और खत्म हो गई जिंदगी!

सीएमओ दफ्तर से फाइल गायब, 8 महीने बाद भी आरोपी बेखौफ सिस्टम कटघरे में।

बृजेन्द्र वीर सिंह

तमसा संकेत, अम्बेडकरनगर। जनपद में एक युवक की संदिग्ध हालात में हुई मौत ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस तंत्र की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला अब सिर्फ कथित इलाज में लापरवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें दबाव, धमकी और सबूतों के गायब होने जैसे आरोप भी जुड़ गए हैं। जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गोलपुर निवासी किरन ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि उनके भाई भारत को 01 मई 2025 को पेट दर्द की शिकायत पर गोलपुर बाजार के एक कथित झोलाछाप डॉक्टर के पास ले जाया गया। आरोप है कि बिना समुचित जांच के कमर में कई इंजेक्शन लगाए गए, जिसके तुरंत बाद युवक के दोनों पैर सुन्न हो गए और हालत तेजी से बिगड़ती चली गई। परिजनों के मुताबिक, स्थिति गंभीर होने पर डॉक्टर ने अपने खर्चे पर इलाज कराने की बात कही, लेकिन बाद में कोई ठोस इंतजाम नहीं किया।

पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई न होने से कई सवाल खड़े हो रहे

- क्या एक आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं?
- क्या जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या मामला फाइलों में ही दबकर रह जाएगा?
- अब निगाहें प्रशासन पर टिकी हैं-देखना होगा कि इस मामले में सख्त कदम उठते हैं या "फाइल गायब" की परतों में सच दबकर रह जाता है।

>> (शेष पेज 04 पर)

200 फीट गहरी खाई में गिरी बस, दो महिलाओं की हुई मौत

31 घायल, कपड़ों से रस्सी बनाकर बाहर निकाला, कंधों पर उठाकर लाए

दुर्घटना

तमसा संकेत, एजेंसी

अजमेर। अजमेर में सवारियों से भरी बस 200 फीट नीचे खाई में गिर गई। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। 31 लोग घायल हो गए। पुष्कर जा रही बस में 33 लोग सवार थे। वे पीसांगन (अजमेर) में मायरा भरने जा रहे थे। इस दौरान पुष्कर घाटी में बस बेकाबू हो गई। हादसा पुष्कर से करीब 3 किलोमीटर पहले रविवार दोपहर करीब 12 बजे हुआ। मौके से गुजर रहे लोगों ने कपड़ों से रस्सी बनाकर घायलों को खाई से बाहर निकाला।

>> (शेष 04 पर)

फिटनेस और इंश्योरेंस, दोनों खत्म

ऑनलाइन RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) देखने पर सामने आया कि मिनी बस (RJ19PA9932) का फिटनेस और इंश्योरेंस, दोनों खत्म हो गए थे। बस का इंश्योरेंस 6 अगस्त 2025 जबकि फिटनेस 31 मार्च 2026 को खत्म हो चुका था।

200 फीट नीचे पेड़ और झाड़ियों में फंसी बस

सीओ ग्रामीण रामचंद्र चौधरी ने बताया- अजमेर से पुष्कर की ओर जाते समय सांझीसर से थोड़ा आगे यह हादसा हुआ है। बस अचानक मेन रोड से खाई में उतर गई। करीब 200 फीट नीचे आकर पेड़ और झाड़ियों में फंस गई।

तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 18 लोगों की मौत

6 घायल, कई मलबे में दबे, 30 मजदूर काम कर रहे थे

दर्दनाक

- विस्फोट में फैक्ट्री के तीन कमरे ढह गए और आसपास की कुछ इमारतों को नुकसान हुआ है।
- फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है।

तमसा संकेत, एजेंसी

विरुधुनगर। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक, हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है।

6 दिन पहले भी धमाके में दो लोगों की मौत हुई थी

इससे पहले 13 अप्रैल को विरुधुनगर सत्तूर के पास सथिरापट्टी इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था। इसमें दो मजदूर की मौत हो गई थी। पांडी नाम के मजदूर की मौके पर झुलसने से मौत हो गई थी। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान करुप्पासामी (33) की मौत हो गई।

>> (शेष पेज 04 पर)

चारधाम यात्रा शुरू, गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट खुले

सुनील/दीपक/नितिन। उत्तराखंड में आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर गंगोत्री और 12 बजकर 35 मिनट पर यमुनोत्री के कपाट खोल दिए गए। गंगोत्री में पहली पूजा पीएम मोदी के नाम की हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस पूजा के खत्म होने के बाद आम लोग अब मां गंगा के दर्शन कर पा रहे हैं।

उधर, मां यमुनोत्री में कपाट खुलते ही काफी देर से दर्शन के लिए खड़े लोगों की भीड़ अब मंदिर की तरफ बढ़ती दिख रही है। वहीं, बाबा केदार की डोली भी अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से फाटा की ओर रवाना हो गई है। बाबा की पंचमुखी डोली 21 अप्रैल को केदारनाथ पहुंचेगी जिसके बाद अगले दिन 22 अप्रैल कपाट खुलेंगे। रविवार दोपहर 3 बजे तक 18 लाख से ज्यादा लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया है।

लखनऊ से सीएम योगी ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया

'जैसे आत्मा वैसे सनातन अमर है'

मुख्यमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को रवाना किया और इसे भारत की आस्था, एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बताया। इस यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश से 1000 से अधिक श्रद्धालु गुजरात स्थित सोमनाथ धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए

धर्मयात्रा

हेमन्त कृष्ण

तमसा संकेत, लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश का शुभारंभ किया। उन्होंने गोमती नगर स्टेशन पर सोमनाथ यात्रा विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का गौरव है कि आज यहां सब कुछ है। काशी की जीवंतता है।

अयोध्या की मर्यादा है। मथुरा वृन्दावन की भक्ति है। प्रयागराज की समरसता है। हम महाकाल जाते हैं तो महाकाल का लोभ। केदारपुरी में जाते हैं तो केदारेश्वर और बद्री विशाल का भव्य मंदिर। रामेश्वरम जाते है तो वहां का धाम, हमको आकर्षित करता है।

>> (शेष पेज 04 पर)

हमारी आस्था को कोई भी डिगा नहीं पायाः योगी

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्ष पहले जिन आक्रांताओं ने राम मंदिर को अपमानित करने का काम किया था। हिन्दुओं की आस्था पर कुठाराघात किया था। क्या वे हमारी आस्था को हटा पाए? डिगा पाए? नहीं, जिन्होंने आस्था पर प्रहार किया था उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। सनातन की आस्था पूरी भव्यता के साथ आज भी आकाश की तरह ऊंचाइयों पर मौजूद है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। केसरिया ध्वज मंदिर में लहरा रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर और मां विंध्यावासनी का भव्य कॉरिडोर बन गया है। दुनिया में सांस्कृतिक आयोजन किस रूप में होना चाहिए उसका प्रतीक महाकुम्भ बना।

10-11 साल पहले कोई सोचता था कि राम मंदिर का निर्माण होगा

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कार्य आजाद भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने आगे बढ़ाया था, यह उसी अभियान का कार्यक्रम है। कोई सोचता था कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा।

'पहले की सरकारों में आस्था और संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया'

मेरठ के रहने वाले पंकज चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम लोगों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रहे हैं। इससे पहले की सरकारों में कभी भी आस्था और संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया गया था। ट्रेन में हर तरह की सुविधा हम लोग को दी जा रही है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को स्मृति चिह्न दिया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मेयर सुषमा खर्कवाल भी मौजूद रहीं।

व्हाइट स्वान आर्ट और सीएसआईआर-आईआईटीआर की ओर से सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। इसके जरिए समाज को एकजुट करने का संदेश दिया।

'यात्रा के दौरान हर जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं'

बिजनौर से आईं रविता राठी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हम लोगों को सोमनाथ की पावन यात्रा के लिए भेजा जा रहा है। हम लोग को सभी तरह की सुविधा दी जा रही हैं। हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं।

ईरानी राष्ट्रपति बोले हम युद्ध नहीं चाहते, सिर्फ आत्मरक्षा कर रहे

'अमेरिका पर भरोसा नहीं'

ईरान बोला- हालात बिगड़ सकते हैं होर्मुज से हमारे जहाज नहीं निकले तो किसी के नहीं गुजरने देंगे

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी । ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान ने रविवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान के परमाणु अधिकारों को रोकने का कोई हक नहीं है।

ईरानी न्यूज एजेंसी ISNA के मुताबिक, पजशकियान कहा, "ट्रम्प कहते हैं कि ईरान अपने परमाणु अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन यह नहीं बताते कि किस जुर्म में।

वह कौन होते हैं किसी देश को उसके अधिकारों से वंचित करने वाले?" पजशकियान का यह बयान ऐसे समय आया है जब सीजफायर की समय सीमा खत्म होने वाली है। अमेरिका-ईरान के बीच बातचीत में अभी भी गतिरोध बना हुआ है। >> (शेष पेज 04 पर)

ईरान बोला- अमेरिका की नाकेबंदी युद्ध अपराध है

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों और तट पर लगाई गई नाकेबंदी सीजफायर का उल्लंघन है। न्यूज एजेंसी AP के मुताबिक, इस्माइल ने कहा कि ईरानी जनता पर सामूहिक सजा थोपना युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर है।

ईरान डेलिगेशन मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा

ईरान का डेलिगेशन मंगलवार को अमेरिका के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। CNN के मुताबिक, इस टीम में पिछली बार की तरह विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ शामिल हो सकते हैं। अगर बातचीत ठीक रही और अमेरिकी राष्ट्रपति डोलाल्ड ट्रम्प इस्लामाबाद आने पर सहमत हुए तो ईरान के राष्ट्रपति भी वहां जा सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की बैठक हो सकती है जिसमें 'इस्लामाबाद घोषणा' पर हस्ताक्षर किया जा सकता हैं।

सम्पादकीय

कभी ईरान अपनी जिद पर अड़ता है तो कभी अमेरिका

ईरान के विदेश मंत्री की ओर से होर्मुज समुद्री मार्ग खोलने की घोषणा को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि ईरानी सेना ने उस पर फिर से अपना पहरा बैठाने का फैसला कर लिया। उसने इस कारण होर्मुज को फिर से बंद करने का फैसला किया, क्योंकि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने पर अड़ा है। साफ है कि पश्चिम एशिया संकट के मामले में कभी ईरान अपनी जिद पर अड़ता है तो कभी अमेरिका।

जब युद्धविराम की शर्तों के तहत होर्मुज खोलने पर सहमति बन गई थी और उसका दायरा लेबनान तक प्रभावी हो जाने के बाद ईरान ने इस समुद्री मार्ग को पूरी तरह खोलने की घोषणा कर दी थी तो फिर अमेरिका को भी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी करने के अपने फैसले से पीछे हट जाना चाहिए था। तब तो और भी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के फैसले का स्वागत किया और दोनों देश दूसरे दौर की शांति वार्ता करने की संभावनाएं भी टटोल रहे हैं।

यह अमेरिका और ईरान के साथ पश्चिम एशिया के लिए ही आवश्यक नहीं है कि दो सप्ताह के अस्थायी युद्धविराम को स्थायी रूप दिया जाए, बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि होर्मुज के बाधित होने के कारण विश्व भर में ऊर्जा संकट गहरा रहा है। वैसे तो इस समुद्री मार्ग के बाधित होने से सबसे अधिक भारत और अन्य एशियाई देश प्रभावित होते हैं, लेकिन इस मार्ग से तेल और गैस की आपूर्ति में कमी आने के नतीजे में उनके दाम बढ़ने का असर पूरे विश्व पर पड़ता है। यह ठीक है कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की अनुमति एक माह के लिए और बढ़ा दी, लेकिन आखिर वह यह तय करने वाला होता कौन है कि किस देश से तेल-गैस खरीदा जा सकता है? अमेरिका अपने स्वार्थों के चलते किसी न किसी ऊर्जा संपन्न देश पर प्रतिबंध लगाता ही रहता है। ईरान, वेनेजुएला और रूस इसके उदाहरण हैं। इसके दुष्परिणाम संबंधित देश के साथ अन्य देश भी भोगते हैं। अमेरिका यह जो मनमानी करता है, उसे चुनौती दी जानी आवश्यक है। यह अच्छा है कि भारत रूस से तेल खरीद मामले में अमेरिका के रवैये की परवाह नहीं कर रहा है। भारत को न केवल अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए हरसंभव कदम उठाने चाहिए, बल्कि खुद को आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी बनाना चाहिए कि अमेरिका किसी तरह का अनुचित दबाव न डालने पाए। अमेरिका और ईरान के बीच लागू अस्थायी युद्धविराम की अवधि जैसे-जैसे करीब आ रही है, उसके स्थायी रूप लेने पर वैसे-वैसे संशय बढ़ रहा है। इस नाजुक युद्धविराम को देखते हुए भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए और अधिक सक्रियता दिखानी होगी। उसे न केवल ऊर्जा आयात के नए विकल्प तलाशने होंगे, बल्कि इसके लिए भी उपाय करने होंगे कि आयातित ऊर्जा पर निर्भरता कम कैसे हो।

अतिक्रमण रोकने में सरकारों की सुस्ती आखिर क्यों

> अतिक्रमण हटाने में सुस्ती का एक और कारण है न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति। कई मामलों में अतिक्रमण करने वाले लोग अदालतों का सहारा लेते हैं और स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं।

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ-साथ एक गंभीर समस्या लगातार गहराती जा रही है, जिसे हम अतिक्रमण के नाम से जानते हैं। अतिक्रमण केवल जमीन पर अवैध कब्जा नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक संसाधनों, सड़कों, फुटपाथों, जल निकायों और सरकारी भूमि के अनियंत्रित उपयोग का प्रतीक बन चुका है। यह समस्या केवल सौंदर्य और व्यवस्था को प्रभावित नहीं करती, बल्कि इससे यातायात, पर्यावरण, सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अतिक्रमण की समस्या सबको दिखाई देती है, फिर भी सरकारों और प्रशासन की प्रतिक्रिया अक्सर धीमी, असंगत और अस्थायी होती है। प्रश्न यह उठता है कि आखिर अतिक्रमण रोकने में सरकारों की सुस्ती क्यों बनी रहती है। भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न समयों पर जारी रिपोर्टों और कार्यक्रमों के संदर्भ में यह तथ्य सामने आता है कि देश की शहरी आबादी लगातार बढ़ रही है और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी, जो कि 2021 के अनुमानों में 35 प्रतिशत से अधिक मानी जा रही है। शहरीकरण की इस तीव्र गति के साथ यदि नियोजन और भूमि प्रबंधन समान गति से न हो, तो अतिक्रमण की समस्या स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। जब लोगों को वैध आवास, व्यापार या आजीविका के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिलता, तो वे अनौपचारिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अतिक्रमण की समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। कई बार अतिक्रमण करने वाले लोग स्थानीय स्तर पर एक बड़े मतदाता वर्ग का हिस्सा होते हैं। ऐसे में राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक के प्रभावित होने का भय रहता है। यह स्थिति प्रशासन को भी निष्क्रिय बना देती है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाव बना रहता है। परिणामस्वरूप अतिक्रमण हटाने के अभियान या तो शुरू ही नहीं होते, या यदि होते भी हैं तो थोड़े समय बाद ठंडे पड़ जाते हैं। दूसरा प्रमुख कारण है प्रशासनिक तंत्र की जटिलता और समन्वय की कमी। भूमि प्रबंधन, नगर नियोजन, पुलिस, राजस्व विभाग और स्थानीय निकाय—सभी का इस विषय में अलग-अलग दायित्व होता है। लेकिन इन विभागों के बीच समन्वय का अभाव अक्सर कार्रवाई को धीमा कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि नगर निगम अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाना चाहता है, तो उसे पुलिस बल की आवश्यकता होती है। यदि पुलिस सहयोग नहीं करती या पर्याप्त बल उपलब्ध नहीं होता, तो कार्रवाई अधूरी रह जाती है। इसी प्रकार, भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद भी कार्रवाई को जटिल बना देते हैं। जब तक मामला न्यायालय में लंबित रहता है, तब तक प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाता। भारत में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या अत्यधिक है, और विधि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 तक देश में विभिन्न स्तरों की अदालतों में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। ऐसे में अतिक्रमण से जुड़े मामलों का भी वर्षों तक समाधान नहीं हो पाता, जिससे समस्या बनी रहती है।

अतिक्रमण का आर्थिक पहलू भी सरकारों की सुस्ती का एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बार अतिक्रमण से अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक गतिविधियाँ जुड़ी होती हैं, जैसे छोटे व्यापारी, ठेला विक्रेता और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। ये लोग अपनी आजीविका के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करते हैं। यदि प्रशासन अचानक अतिक्रमण हटाता है, तो इन लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित होती है, जिससे सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो सकता है। इस कारण सरकारें अक्सर कठोर कार्रवाई से बचती हैं और समस्या को टालने की प्रवृत्ति अपनाती हैं।

भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत यह स्वीकार किया गया है कि शहरी गरीबों के लिए आजीविका के अवसरों की कमी एक बड़ी चुनौती है। जब तक इन लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक अतिक्रमण हटाना स्थायी समाधान नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य से, पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास अक्सर अपर्याप्त और धीमे होते हैं, जिससे समस्या जस की तस बनी रहती है।

अतिक्रमण की समस्या में भ्रष्टाचार भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार स्थानीय स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी अतिक्रमण को नजरअंदाज करते हैं या उससे लाभ उठाते हैं। अवैध कब्जों के बदले में रिश्वत लेना या राजनीतिक संरक्षण देना एक आम शिकायत रही है। पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी इस समस्या को और बढ़ाती है। जब तक प्रशासनिक तंत्र में ईमानदारी और सख्ती नहीं होगी, तब तक अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है।

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अतिक्रमण एक गंभीर खतरा है। जल निकायों, नदियों और हरित क्षेत्रों पर अतिक्रमण के कारण बाढ़, जलभराव और प्रदूषण की समस्याएँ बढ़ती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि शहरी जल निकायों के अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण जल गुणवत्ता में गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, कई शहरों में नालों और झीलों पर अतिक्रमण के कारण वर्षा के समय जल निकासी बाधित हो जाती है, जिससे शहरी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है।

अतिक्रमण रोकने में सुस्ती का एक कारण जन जागरूकता की कमी भी है। जब तक नागरिक स्वयं यह नहीं समझेंगे कि अतिक्रमण उनके ही जीवन को प्रभावित करता है, तब तक इस समस्या का समाधान कठिन है। लोग अक्सर अपनी सुविधा के लिए सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करते हैं, लेकिन इसके दीर्घकालिक दुष्परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह मानसिकता भी अतिक्रमण को बढ़ावा देती है।

तकनीकी संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग भी इस समस्या को बढ़ाता है। आज के समय में भौगोलिक सूचना प्रणाली, उपग्रह चित्रण और डिजिटल मानचित्रण के माध्यम से भूमि उपयोग की निगरानी की जा सकती है, लेकिन इन तकनीकों का व्यापक और प्रभावी उपयोग अभी भी सीमित है। यदि इनका सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो अतिक्रमण की पहचान और रोकथाम अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है।

समाधान की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सरकारें अतिक्रमण को केवल एक प्रशासनिक समस्या न मानकर इसे एक समग्र सामाजिक-आर्थिक चुनौती के रूप में देखें। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सबसे पहले, शहरी नियोजन को मजबूत करना होगा और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि उपयोग की स्पष्ट और व्यावहारिक योजनाएँ बनानी होंगी। इसके साथ ही, अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित और निरंतर अभियान चलाने होंगे, न कि केवल प्रतीकात्मक कार्रवाई।

पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि अतिक्रमण करने वाले लोगों को सम्मानजनक विकल्प मिल सके। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाना होगा और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। न्यायिक प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाना भी आवश्यक है, ताकि अतिक्रमण से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान हो सके।

डॉ शैलेश शुक्ला

दोनों सदनों ने इसकी...

राजेश श्रीवास्तव

प्रधानमंत्री जी कम से कम मातृ शक्ति को तो सियासत का केंद्र न बनाइये

कल जब सदन में महिला आरक्षण संशोधन बिल पास नहीं हो सका तभी से यह उम्मीद लग रही थी कि भाजपा जिस मकसद से इसे लायी थी उसका खुलासा और शुभारंभ कब होगा। और उम्मीद के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व की भांति रात्रि साढ़े आठ बजे अचानक प्रकट हुए लेकिन इस बार देश की जनता की धड़कने धक-धक नहीं कर रहीं थीं क्योंकि सभी को अंदाजा था कि प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आयेंगे और विपक्षी दलों को कोसेंगे और उन्हें महिलाओं की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहरायेंगे। अब यहीं से भाजपा की महिला आरक्षण बिल पर सियासत शुरू हो गयी। अरे प्रधानमंत्री जी आप ने तब देश की जनता से बात करना उचित नहीं समझा जब आपकी जनता दुनिया के बीच मचे युद्ध को लेकर सशंकित थी, तब भी नहीं समझा जब जनता गैस की लाइनों में लगी थी। आपने तब भी उचित नहीं समझा जब पाकिस्तान ने युद्ध में समझौत कर लिया और आपने तो उस पर भी बात नहीं की कि कैसे ईरान में होर्मुज पार कर रहे दो भारतीय टैंकरों पर गोलीबारी हुई। आपका राष्ट्र प्रेम तब भी नहीं जागा। और जागा तो इस बात के लिए कि महिलाओं को 2011 की जनगणना के मुताबिक आरक्षण नहीं दे सके। आपने वही सब बोला जो आप और आपके नेता सदन में दो दिन बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपको बिल लाने की क्या जरूरत है महिलाओं के आरक्षण के लिए आप सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं बढ़-चढ़कर दीजिये महिलाओं को टिकट, महिलाओं को हिस्सेदारी, कैबिनेट समितियों में योगदान, सीबीआई में बढ़ाइये संख्या। इसके लिए बिल की क्या जरूरत है। प्रधानमंत्री जी आपके कार्यकाल में पहली बार कोई बिल गिरा है इसलिए आप भावुक हो गये लेकिन जब मणिपुर में महिलाओं की इज्जत तार-तार हो रही थी तब आपका महिला प्रेम नहीं जागा, जब महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था। आपने कहा कि कहा, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया। मैं इसके लिए सभी माताओं-बहनों का क्षमाप्रार्थी हूं। हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जब दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति और देश को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है।' आपने चार दलों- कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा पर विशेषकर निशाना साधा। इसी के साथ द्रमुक को आड़े हाथ लेते हुए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल का जिक्र किया।

क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। प्रधानमंत्री जी कब तक सियासत होगी, जनता सब जानती है। आपका हर कदम राजनीतिक होता है। माना आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपका हर कदम भी सियासत का होगा। लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं जनता के प्रति भी आपकी संवेदना होनी चाहिए। जब देश में बड़े मुद्दे आते हैं तब आप खामोश हो जाते हैं और जब सियासत की बारी आती है तो आप मुखर। आपने यह संदेश देने की कोशिश बखूबी की है कि भाजपा तो महिलाओं को जल्द आरक्षण देना चाहती थी, लेकिन विपक्ष की वजह से ऐसा नहीं हो सका। आपको अगर वाकई में सशक्त करना है तो जो मौजूदा 543 सीटें है उसमें से 33 फीसदी सीटें महिलाओं को दे दीजिए। शायद ये तीन दिन का सत्र केवल नैरेटिव बिल्डिंग के लिए ही था। सच में ये बहुत ही दुखद है। बिल 2023 में पास हो चुका था। दोनों सदनों ने इसकी मंजूरी दे दी थी। अगर सरकार वाकई में चाहती थी 2024 में इस पर काम शुरू कर देती। ये बिल बैक डोर से परिसीमन को लागू करने के लिए लाया गया था। डिलिमिटेशन पर अगर आप बिल पास करना चाहते तो पहले आप विपक्ष से चर्चा करते। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि विपक्ष पर महिला विरोधी होने का तमगा चिपकाना सही है, अब जनता जाग गयी है और वह आपके सियासी तीर समझती है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने 'नारी शक्ति' की जो लकीर खींची है, उसे बीजेपी आज तक नहीं छू पाई है। इंदिरा गांधी वह नेतृत्व थीं, जिन्होंने 1971 में बिना किसी इवेंट मैनेजमेंट के पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। आज जब मोदी सरकार अमेरिकी दबाव (ट्रम्प शासन) के आगे रणनीतिक स्वायत्तता खोती दिखती है, तो इंदिरा की वह 'शक्ति' याद आती है जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया था। जबकि प्रतिभा पाटिल को देश को पहली महिला राष्ट्रपति देने का श्रेय भी कांग्रेस को जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी को कांग्रेस ने ही बनाया था। कांग्रेस की शीला दीक्षित ने 15 साल शासन किया और दिल्ली को विकास की नयी ऊंचाई दी। 1993 में राजीव गांधी द्वारा लाया गया 73वां और 74वां संविधान संशोधन ही वह आधार था जिसने आज 21 राज्यों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। इसीलिए जब राहुल गांधी 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' की खामियों पर उंगली उठाते हैं, तो उनका डर वास्तविक लगता है।

अशोभनीय...

सुनीता नारायण

संघर्ष के दौर में ऊर्जा

ईरान के खिलाफ विनाशकारी अमेरिका-इजरायल संघर्ष ने दुनिया भर में ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर दिया है। अमीर और गरीब दोनों तरह के देशों की सरकारें अपने लोगों को आने वाले भीषण समय के बारे में सचेत कर रही हैं, जैसा इस पीढ़ी ने पहले कभी नहीं देखा। ऊर्जा/ईंधन की अविश्वसनीय कमी, राशनिंग और यहां तक कि कारों और हवाई जहाजों के ईंधन खत्म होने की आशंका। सवाल यह है कि भविष्य का ऊर्जा मानचित्र कैसा दिखेगा? जैसा कि मैं यह पूछ रही हूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उन हत्याओं, हजारों जानों के नुकसान और उस संवेदनहीन विनाश को हल्के में न लें जिसे हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। इस ऊर्जा व्यवधान द्वारा दुनिया में लाए गए वास्तविक दर्द को भी कम करके न आंकें। कई देश रसोई ईंधन (एलपीजी) की कमी का सामना कर रहे हैं, और परिवार इसे किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। ज्यादातर देशों में, विशेष रूप से हमारी दुनिया में, ईंधन आयात व्यापार घाटे पर सबसे अधिक भार है और इस स्थिति में, तेल की बढ़ती कीमतों का अर्थव्यवस्थाओं पर अपंग कर देने वाला प्रभाव पड़ता है। वहीं वैश्विक उर्वरक आपूर्ति में आसन्न कमी से किसानों पर भारी मार पड़ने की आशंका है- वे जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन से प्रेरित चरम मौसम और विकृत वैश्विक खाद्य कीमतों से जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर, दुनिया घुटनों पर है- पसंद से नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ इस संवेदनहीन अमेरिका-इजरायल संघर्ष के प्रति अपनी डरपोक और दयनीय प्रतिक्रिया के कारण। नियम-आधारित व्यवस्था और उसकी सारी नैतिकता तार-तार हो चुकी है। यह हमारे सामने सवाल छोड़ता है कि इस झटके का ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस अशोभनीय संघर्ष से पहले भी दुनिया ऊर्जा संक्रमण के बीच में थी-बिजली के लिए कोयले को लगातार नवीकरणीय ऊर्जा से बदलना और वाहनों में पेट्रोल और डीजल के उपयोग को विस्थापित करना। अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की मार्च 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत तक, दुनिया की स्थापित बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत थी। दिलचस्प बात यह है कि यह ऊर्जा संक्रमण केवल वहां नहीं हो रहा था जहां उम्मीद की जा सकती थी-जैसे चीन या यूरोप। थिंक टैंक 'एंबर' की एक रिपोर्ट में पाया गया कि 74 सबसे जलवायु-संवेदनशील देश 'इलेक्ट्रो-टेक' को तेजी से अपना रहे थे, इसलिए नहीं कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रति चिंतित थे, बल्कि इसलिए कि यह तेज, सस्ता और अधिक विश्वसनीय था। ये देश जीवाश्म ईंधन को छोड़कर सीधे नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ सकते हैं।

रिपोर्ट कहती है, 'सौर उत्पादन में नामीबिया और टोगो, बैटरी बिक्री में जार्डन और किर्गिस्तान, और ईवी अपनाने में नेपाल और श्रीलंका आगे हैं।'

वर्तमान व्यवधान ने ऊर्जा आयात की लागत बढ़ा दी है और देशों को ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता के प्रति जागरूक कर दिया है। तेल और गैस के बाजारों को हासिल करने के लिए फिर से होड़ मची है। यह देशों को अपने स्वयं के संसाधनों- कोयला से लेकर चारकोल तक- का अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो दोनों ही प्रदूषणकारी हैं।

खतरनाक ढंग से विभाजित होती दुनिया

फिलहाल अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। अमेरिका और ईरान, दोनों ने इसका श्रेय पाकिस्तान को दिया। बाद में यह स्पष्ट हुआ कि पाकिस्तान की भूमिका मुख्यतः संदेशवाहक की थी। इस पर भारत की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई और कुछ हलकों में यह आलोचना सामने आई कि उसकी भूमिका को पर्याप्त मान्यता नहीं मिली। हालांकि पाकिस्तान सुन्नी बहुल है, जबकि ईरान शिया बहुल। इसके बावजूद इस दौरान कुछ देशों ने कहा कि वे स्वयं को शिया या सुन्नी के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक रूप से मुसलमान के रूप में देखते हैं और वैश्विक स्तर पर उनके हित परस्पर जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में कश्मीर में ईरान के समर्थन में धन एकत्र करने की गतिविधियां सामने आईं, जबकि भारत का इस संघर्ष से कोई संबंध नहीं। हाल में सैमुअल पी. हंटिंगटन की पुस्तक 'क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन्स' फिर से पढ़ी। वे लिखते हैं, 'सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एकध्रुवीय हो गया है। आने वाले समय में संघर्ष राष्ट्रों के बीच नहीं, बल्कि सभ्यताओं के बीच होगा। महाशक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा सभ्यताओं के टकराव के रूप में प्रकट होगी। सभ्यताओं का यह संघर्ष विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यह संघर्ष किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक स्तर पर फैल सकता है। आज लोग आधुनिक पहचान के साथ-साथ अपनी पारंपरिक पहचान को भी पुनः खोज रहे हैं। इसी कारण वे नई परिस्थितियों के साथ-साथ पुराने द्वंद्वों को भी बनाए हुए हैं और उन्हें भूलने के लिए तैयार नहीं हैं। भविष्य में संघर्ष केवल आर्थिक असमानताओं जैसे-अमीर और गरीब के बीच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच अधिक तीव्र रूप में सामने आएगा।

यह इतिहास का एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण दौर हो सकता है।' सभ्यताओं के रूप में वे पश्चिमी, दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी, इस्लामिक, सिनिक, हिंदू, आर्थोडाक्स, बौद्ध और जापानी सभ्यताओं का उल्लेख करते हैं। अमेरिकी राजनीतिज्ञ हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था कि 21वीं सदी में छह बड़ी शक्तियां होंगी-अमेरिका, यूरोप, चीन, जापान, रूस और संभवतः भारत। वहीं सैमुअल हंटिंगटन ने चीन, वियतनाम और जापान को अलग-अलग सभ्यताओं के रूप में देखा।

क्षमा शर्मा।

जरा हटके

लंबे संघर्ष और ...

विवेक रंजन श्रीवास्तव

महिला आरक्षण की अधूरी यात्रा और लोकतंत्र

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताक़त उसकी विविधता और समावेशिता है। लेकिन जब लोकसभा में ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का संविधान संशोधन वर्षों तक पारित नहीं हो सका, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारा लोकतंत्र वास्तव में आधी आबादी को बराबरी का अवसर देने की इच्छा रखता है।

विधेयक का महत्व

महिला आरक्षण विधेयक केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं था, बल्कि यह भारतीय राजनीति में समानता और न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम होता। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें मिलतीं तो उनकी आवाज़ अधिक मज़बूती से गूँजती। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर नीतियाँ अधिक संवेदनशील और व्यावहारिक बनतीं।

आज भी संसद में महिलाओं की संख्या 15% से कम है। यह आँकड़ा बताता है कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी सीमित है। आरक्षण से यह अंतर मिटाने का अवसर मिलता।

असफलता के कारण

विधेयक पारित न हो पाने के पीछे कई कारण रहे जिनमें राजनीतिक असहमति प्रमुख है। कुछ दलों ने जनगणना आधारित सीटों के पुनर्वितरण (परिसीमन) पर आपत्ति जताई। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को दो धारी तलवार पर खड़ा कर दिया। उनके लिए संविधान संशोधन हेतु जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाना कठिन साबित हुआ। सपा जैसे कुछ दलों को आशंका थी कि आरक्षण से उनके पारंपरिक वोट बैंक प्रभावित होंगे, इसलिए वे विरोध में रहे। इन कारणों ने मिलकर एक ऐतिहासिक अवसर का गर्भपात कर दिया।

2023 का नया अध्याय

लंबे संघर्ष और बहस के बाद 2023 में संसद ने आखिरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। इसमें यह प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें मिलेंगी, लेकिन यह आरक्षण परिसीमन (delimitation) और जनगणना के बाद ही लागू होगा। इस शर्त ने इसे एक अधूरी जीत बना दिया है, क्योंकि वास्तविक प्रभाव तब तक नहीं दिखेगा जब तक नई जनगणना और सीटों का पुनर्वितरण पूरा नहीं होता।

समकालीन परिप्रेक्ष्य

2024 के आम चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी, लेकिन प्रतिनिधित्व अब भी सीमित रहा। महिला संगठनों ने 2023 के विधेयक को ऐतिहासिक लेकिन अधूरा कहा। कई राजनीतिक दलों ने इसे समर्थन दिया, पर साथ ही यह मांग भी उठी कि इसे शीघ्र लागू किया जाए ताकि केवल कागज़ी प्रावधान न रह जाए।

महिला आरक्षण विधेयक का अधूरा रहना और फिर विलंबित रूप से पारित होना कई स्तरों पर असर डालता है। महिला नेतृत्व का अवसर फिलहाल टल गया लगता है। महिला संगठनों और नागरिक समाज में गहरी निराशा है। राजनीतिक दलों पर इसे शीघ्र लागू करने का दबाव बढ़ेगा।

लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक का अधूरा रहना केवल एक विधायी पराजय नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की अधूरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राजनीति व्यापक राष्ट्रहित से बड़ी सिद्ध हुई।

जब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी, तब तक नीतियाँ समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएँगी। भारत की आधी आबादी को बराबरी का अधिकार देना केवल संवैधानिक दायित्व नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी भी है। यह विधेयक पारित होना हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी राजनीति वास्तव में समावेशी है।

महिला आरक्षण विधेयक का अधूरा रहना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक चुनौती है। यह आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल

लोभ से पाप प्रवृत्त होता हैं

लोभ पाप का बाप है जो पल पल में संताप पैदा करता है । लोभ में अशांति, भय व तृष्णा आदि - आदि सब विद्यमान है । ऐसे में संतोष ही एक मात्र सुखी जीवन शैली का एक सशक्त व सुंदर समाधान है । मन में प्रश्न उठा कि पाप का परिणाम तो सदा बुरा है । वह इसका परिणाम कभी इस लोक में नहीं तो परलोक में तो निश्चित ही कभी न कभी यह मिल जाता हैं । फिर भी लोग पाप क्यों करते हैं ? इसलिए जवाब है क्योंकि पाप करते वक्त आदमी मति भ्रमित रहता है कि अप्रमित सुख मिलेगा । ध्यान देने योग्य है कि पाप सुख देगा यह जरूरी नहीं हैं । यह केवल सुख का प्रलोभन ही देता है । और बहुत बार वह सुख मिलता भी नहीं हैं । उसके अनेक कारण यहां-वहां कहीं न कहीं बन जाते हैं। अंत में मृगमरिचिका बन कर तथाकथित सुख रह जाता है जिसने इस तथ्य को समझ लिया उसने बहुत बड़े सत्य को जान लिया। मन की लोभी तृष्णा का कोई अंत नहीं होता हैं । वह जैसे-जैसे हमको सोचा हुआ हाशिल होता है वैसे-वैसे और नयी चाहत हमारी बढ़ने लगती है। वह जिसका जीवन में कभी अंत ही नहीं होता हैं । हमारे जीवन की इस आपा-धापी में जीवन के स्वर्णिम दिन कब बीत जाते हैं उसका हमें भान भी नहीं रहता हैं । वह आगे जीवन में कभी सपने अधूरे रह गये तो किसी के मुँह से यही निकलता है कि कास अमुक काम मैं अमुक समय कर लेता।उनके लिये बस बचता है तो किसी के कास तो किसी के जीवन में अगर आदि - आदि । हमारे को जैसे - जैसे लाभ होता हैं वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता हैं । वह कुछ प्राप्त होने हम मानव सोचते हैं कि कुछ और मिले, आगे और मिले । लोभ एक ऐसी वृत्ति हैं , जिसके उभरने पर हम मनुष्य अनेक पापों में प्रवृत्त हो सकतें हैं । हम विद्वत्-संत समागम में जाते हैं तो वहां यह सब सुनते हैं। पर वहाँ से निकलते ही हम पल्ला झाड़ देते हैं तो फिर संत समागम करने से हमको क्या लाभ हुआ ? वह और तो और छोटी-छोटी बातों पर तू-तू मैं-मैं करते भी हम नहीं सकुचाते हैं । वह मन को राग-द्वेष से भर लेते हैं। लोभ पाप का बाप है जो पल पल में संताप पैदा करता है । लोभ में अशांति, भय व तृष्णा आदि सब विद्यमान हैं । ऐसे में संतोष ही एक मात्र सुखी जीवन शैली का एक सशक्त व सुंदर समाधान है । वृत्ति होने पर प्रवृत्ति होती हैं । मनुष्य हिंसा करता हैं तो उसका कारण उसके भीतर वृत्ति का होना हैं । प्रवृत्ति होने पर फिर उसका परिणाम भी आता हैं ।

प्रदीप छाजेड़

2027 वनडे वर्ल्ड कप तक संभालेंगे जिम्मेदारी, टीम इंडिया ने 3 आईसीसी खिताब जीते

चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा

निर्णय

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में अजीत अगरकर का कार्यकाल एक साल के लिए और बढ़ा दिया है। अब वे 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप तक इस पद पर बने रहेंगे।

इससे पहले मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि अजीत ने BCCI से अपने क्रॉन्ट्रैक्ट को 2027 वनडे वर्ल्ड कप बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि एनआई को BCCI के एक वरिष्ठ सूत्र ने बताया कि अजीत का कार्यकाल रिन्यू किया गया है, एक्सटेंड (नहीं। वे अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर चौथे साल के लिए पद पर बने रहेंगे। BCCI के नियमों के मुताबिक, एक चयनकर्ता जूनियर या सीनियर चयन समिति में अधिकतम चार साल तक रह सकता है। अगरकर का मौजूदा कार्यकाल पहले ही बढ़ाया जा चुका है। 2025 IPL से पहले BCCI ने उनका कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए बढ़ाकर जून 2026 तक कर दिया था।

अगरकर के कार्यकाल में भारत ने तीन खिताब जीते

अजीत अगरकर का पिछला कार्यकाल बेहद सफल रहा। अक्टूबर 2023 से मार्च 2026 के बीच उनके द्वारा चुनी गई भारतीय टीमों ने चार ICC टूर्नामेंट्स के फाइनल में जगह बनाई। इनमें से भारत ने तीन खिताब अपने नाम किए। 2024 और 2026 के टी-20 वर्ल्ड कप तथा 2025 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी। इसके अलावा, टीम इंडिया 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची थी, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा।

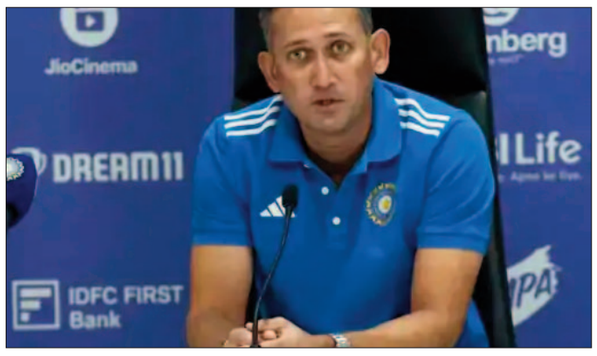

अगरकर के कार्यकाल में टीम इंडिया 2024 और इस साल टी-20 वर्ल्ड कप और पिछले साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी।

2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 'कंटिन्यूटी' पर फोकस

अगला वनडे वर्ल्ड कप 2027 में होना है। BCCCI चाहता है कि टीम की कोर और चयन प्रक्रिया में स्थिरता बनी रहे। अगरकर का कार्यकाल बढ़ने का मतलब है कि वे अगले वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार करने के मिशन पर काम जारी रखेंगे। बोर्ड का मानना है कि इस समय चयन समिति के नेतृत्व में बदलाव करना टीम की लय को बिगाड़ सकता है।

सीएसके ने आयुष म्हात्रे के साथ जो किया वो भारतीय दिग्गज को नहीं आया रास

नई दिल्ली। चेन्नई सुपर किंग्स के युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे चोटिल हो गए हैं। शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में आयुष को चोट लगी थी। इसे लेकर भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने फ्रेंचाइजी पर सवाल उठाए हैं। अश्विन भी चेन्नई के लिए खेल चुके हैं। चेन्नई कल के मैच में दूसरी पारी खेल रही थी। पारी के पांचवें ओवर के दौरान आयुष ने जब दो रन लेने की कोशिश की तभी उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। फिजियो ने उन्हें देखा। आयुष ने फिर दर्द के बाद भी बल्लेबाजी की और फिर 17 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट होकर चले गए।

मैच के दौरान चेन्नई के टीम मैनेजमेंट ने जो किया वो देख अश्विन को गुस्सा आ गया। आयुष ने अपने घुटने पर पट्टी बांधते हुए बैटिंग की। फिजियो दो बार उनको देखने आए, इसके बाद भी चेन्नई ने उनको बाहर नहीं बुलाया।

कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने उनको सिंगल रन के लिए भी बुलाया था। ये सब देख अश्विन को गुस्सा आ गया। अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा,आयुष म्हात्रे को चोट लगी है। मुझे उम्मीद है कि वह वापसी करेंगे, लेकिन जैसा नजर आ रहा है मुझे लग रहा है कि उन्हें ठीक होने में लंबा समय लग सकता है।अश्विन ने कहा, जब वह बल्लेबाजी करने आ रहे थे तब वह घुटने पर पट्टी बांधे हुए थे। दो-तीन मैचों से वह इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं। लोग पूछ रहे थे कि उन्हें बतौर इम्पैक्ट प्लेयर क्यों खिलाया जा रहा है? चोट इसकी वजह लग रही है। अश्विन ने कहा कि आयुष को खुद मैदान से बाहर चले जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस पूरी स्थिति को चेन्नई के मैनेजमेंट ने जिस तरह से संभाला वो हैरान करने वाली बात है। उन्होंने कहा, ऋतुराज को क्रैम्प हो सकते हैं क्योंकि वह फील्डिंग नहीं कर रहे थे। अगर उन्हें फील्डिंग किए बिना ही क्रैम्प आ रहे हैं तो फिर हमें उनके डिहायड्रेशन को देखना होगा। वह बुरी तरह से लंगड़ा रहे थे। उन्हें रिटायर्ड हो जाना चाहिए थे।

दुनियाभर में कमाई 1748.91 करोड़ हुई, पुष्पा 2 को पीछे छोड़ा, सिर्फ दंगल और बाहुबली 2 आगे

तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग भारतीय फिल्म बनी धुरंधर 2

- 19 मार्च (गुरुवार) को धुरंधर 2 दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।
- धुरंधर फ्रेंचाइजी में रणवीर सिंह ने एक भारतीय जासूस का रोल प्ले किया है। जबकि दोनों ही पार्ट का डायरेक्शन आदित्य धर ने किया है।

नई दिल्ली, एजेंसी

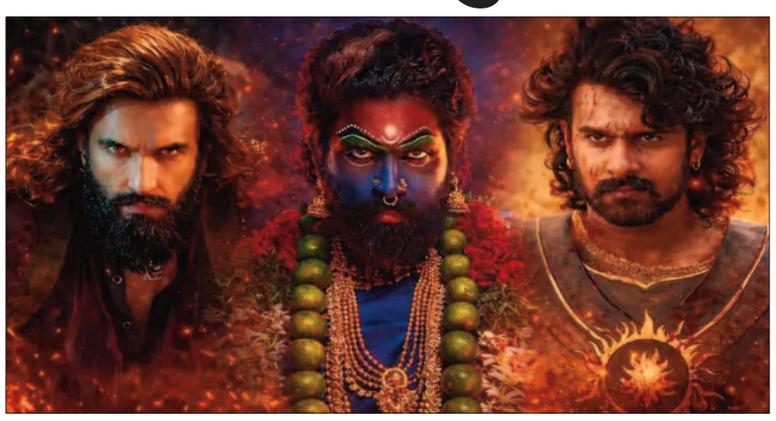

धुरंधर 2 दुनिया भर में तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। फिल्म की दुनिया भर में कमाई 1,748.91 करोड़ रुपए हो गई।

इसने 1,742.10 करोड़ रुपए कमाने वाली अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को पीछे छोड़ दिया। अब यह सिर्फ दंगल (2070 करोड़) और बाहुबली 2 (1,788.06 करोड़) से पीछे है। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रिलीज के 31वें दिन भारत में 4.65 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। फिल्म का कुल भारत नेट कलेक्शन अब 1,110.47 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 1,329.31 करोड़ रुपए हो गया। ग्रॉस कलेक्शन टिकट से कुल कमाई और नेट कलेक्शन टैक्स के बाद की कमाई होती है। ओवरसीज में फिल्म ने 31वें दिन 1.10 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 419.60 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं, फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 1,748.91 करोड़ रुपए हो चुका है।

धुरंधर को शानदार रिस्पॉन्स मिला था

धुरंधर के पहले पार्ट ने भारत और अंतरराष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और दुनियाभर में करीब 1,307 करोड़ रुपए कमाए। भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 1,005.85 करोड़ रुपए रहा, जबकि नेट कलेक्शन लगभग 840 करोड़ रुपए हुआ। विदेशी बाजारों में भी फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। ओवरसीज में इसने करीब 299.5 करोड़ रुपए कमाए। अमेरिका और कनाडा में 193.06 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर बाहुबली 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ा।

फिल्म की कमाई में पांचवें हफ्ते में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन वीकेंड पर इसमें हल्की बढ़त हुई। 30वें दिन जहां फिल्म ने 2.70 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था, वहीं 31वें दिन यह बढ़कर 4.65 करोड़ रुपए हो गया।

फिल्म के हिंदी वर्जन ने 31वें दिन 4.50 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा कलेक्शन किया, जबकि तमिल में 6 लाख रुपए, तेलुगु में 7 लाख रुपए और कन्नड़ में 2 लाख रुपए का नेट कलेक्शन हुआ।

अब बिंदी-तिलक पहन सकेंगे कर्मचारी, कंपनी ने जारी की नई इन-स्टोर स्टाइल गाइडलाइन

लेंसकार्ट ने ड्रेस कोड विवाद पर माफी-मांगी

विरोध

नई दिल्ली, एजेंसी

आईवियर रिटेलर कंपनी लेंसकार्ट ने सोशल मीडिया पर भारी विरोध के बाद पब्लिकली माफी मांगी है। इसके अलावा कंपनी ने अब एक नई और पारदर्शी 'इन-स्टोर स्टाइल गाइड' जारी की है, जिसमें कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अपने धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकों को पहनने की पूरी अनुमति दी गई है।

लेंसकार्ट की नई पॉलिसी में अब बिंदी, तिलक, सिंदूर, कलावा, मंगलसूत्र, कड़ा, हिजाब और पगड़ी जैसे आस्था के प्रतीकों को शामिल किया गया है। कंपनी ने X पर बयान जारी कर कहा कि वे अपनी गाइड-लाइंस को सार्वजनिक और पारदर्शी बना रहे हैं ताकि ग्राहकों और समुदाय की चिंताओं को दूर किया जा सके। लेंसकार्ट की एम्प्लॉई ग्रूमिंग पॉलिसी का एक डॉक्युमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कॉर्पोरेट जगत में कंपनियां अपने कर्मचारियों के ड्रेस कोड और व्यवहार के लिए कुछ नियम बनाती हैं, जिसे ग्रूमिंग पॉलिसी कहा जाता है। इसका उद्देश्य ब्रांड की एक समान पहचान बनाना होता है, लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में इसमें धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना अनिवार्य माना जाता है।

लेंसकार्ट बोला- हम भारतीयों के लिए बने हैं

कंपनी ने अपने नए बयान में कहा कि लेंसकार्ट भारत में, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बना है।

2,400 से ज्यादा स्टोर्स ऐसे लोगों द्वारा चलाए जाते हैं जो अपनी परंपराओं को साथ लेकर आते हैं।

कंपनी ने वादा किया है कि भविष्य की हर ट्रेनिंग और पॉलिसी में सभी की वैल्यूज का ध्यान रखा जाएगा।

लेंसकार्ट की एम्प्लॉई ग्रूमिंग पॉलिसी का एक डॉक्युमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

विवाद की वजह, वायरल हुआ पुराना डॉक्युमेंट

यह पूरा विवाद इस हफ्ते की शुरुआत में तब शुरू हुआ जब लेंसकार्ट की 'एम्प्लॉई ग्रूमिंग पॉलिसी' का एक डॉक्युमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें कर्मचारियों को बिंदी और तिलक जैसे धार्मिक प्रतीकों को पहनने से रोका गया था। इसके बाद इंटरनेट पर कंपनी के बहिष्कार की मांग उठने लगी थी।

फाउंडर पीयूष बंसल ने दी सफाई

विवाद बढ़ता देख कंपनी के फाउंडर पीयूष बंसल ने दखल देते हुए स्पष्ट किया कि वायरल हुआ डॉक्युमेंट एक पुराना था और यह कंपनी के वर्तमान रुख को नहीं दर्शाता। बंसल ने कहा कि हमारी पॉलिसी में धार्मिक अभिव्यक्ति के किसी भी रूप पर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने इस भ्रम की स्थिति के लिए माफी भी मांगी है।

'इरान ने थोड़ी होशियारी दिखाई'

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकी पर बोले ट्रंप

नई दिल्ली, एजेंसी

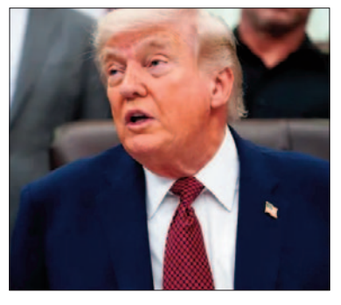

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भविष्य को लेकर अपने बदलते रुख से अमेरिका को ब्लैकमेल न करे। यह चेतावनी तब आई जब तेहरान ने एक बार फिर इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद करने की घोषणा कर दी। ओवल ऑफिस से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम उनसे बात कर रहे हैं। उन्होंने फिर से जलडमरूमध्य बंद करने की बात की। जैसा कि वे सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन वे हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ट्रंप ने ईरान के साथ किसी समझौते को लेकर आशावादी रुख भी दिखाया। उन्होंने कहा कि ईरान थोड़े चालाक बन रहे हैं, जैसा कि वे पिछले 47 सालों से करते आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "बातचीत वास्तव में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। हम देखेंगे, लेकिन आज दिन के अंत तक हमें कुछ जानकारी मिल सकती है।" ईरान की सैन्य कमान ने बयान में कहा कि वाशिंगटन ने ईरान के बंदरगाहों से आने-जाने वाले जहाजों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। बयान में कहा गया, "जब तक अमेरिका ईरान आने वाले सभी जहाजों के लिए आवाजाही की स्वतंत्रता बहाल नहीं करता, तब तक हॉर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिति सख्ती से नियंत्रित रहेगी।" शनिवार सुबह ईरानी सरकारी टीवी ने सैन्य केंद्रीय कमान का हवाला देते हुए बताया कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य का नियंत्रण अपनी पिछली स्थिति में लौट आया है और यह सशस्त्र बलों के सख्त प्रबंधन एवं नियंत्रण में है। ईरान ने इसके लिए अमेरिका की जारी नाकेबंदी को जिम्मेदार ठहराया।

नए प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा ईरान

इस बीच, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने बयान जारी कर कहा कि देश अमेरिका से प्राप्त नए प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है। साथ ही उसने चेतावनी दी कि उसके वार्ताकार वाशिंगटन के साथ कोई समझौता या रियायत नहीं करेंगे।

परिषद ने कहा, "हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेना के कमांडर की मध्यस्थता में तेहरान में अमेरिका द्वारा नए प्रस्ताव पेश किए गए हैं, जिनकी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान वर्तमान में समीक्षा कर रहा है और अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। ईरान का वार्ता प्रतिनिधिमंडल जरा सा भी समझौता, पीछे हटना या नरमी नहीं बरतेगा और ईरानी राष्ट्र के हितों की पूरी ताकत से रक्षा करेगा।"

एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 9% बढ़कर 19,221 करोड़ हुआ

मार्च तिमाही में रेवेन्यू भी 5% बढ़ा, बैंक हर शेयर पर 13 का डिविडेंड देगा

मुंबई, एजेंसी

देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4) के नतीजे जारी कर दिए हैं। 31 मार्च 2026 को खत्म हुई इस तिमाही में बैंक का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 9% बढ़कर 19,221 करोड़ रुपए रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 17,616 करोड़ रुपए था।

बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 13 रुपए प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके भुगतान के लिए रिकॉर्ड डेट 19 जून 2026 तय की गई है। इससे पहले बैंक अगस्त 2025 में 2.5 रुपए प्रति शेयर का स्पेशल अंतरिम डिविडेंड भी दे चुका है। इस तरह निवेशकों को पूरे साल में कुल 15.5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा।HDFC बैंक का कुल नेट रेवेन्यू सालाना आधार पर 5% बढ़कर 46,280 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल मार्च तिमाही में यह 44,090 करोड़ रुपए था।

बैंक की मुख्य आय यानी नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) भी 3.2% बढ़कर 33,080 करोड़ रुपए रही। बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) कुल एसेट्स पर 3.38% दर्ज किया गया। चौथी तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। बैंक का ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) घटकर 1.24% से 1.15% पर आ गया है। वहीं नेट NPA मार्च 2026 तक 0.38% रहा। बैंक ने इस तिमाही के लिए प्रोविजंस और कंटिंजेंसी के तौर पर 2,610 करोड़ रुपए अलग रखे हैं। बैंक का टोटल क्रेडिट कॉस्ट रेश्यो 0.35% रहा।

बैंक के औसत डिपॉजिट्स में अच्छी बढ़त देखी गई है। मार्च 2026 तिमाही में औसत डिपॉजिट्स 28.5 लाख करोड़ रुपए रहे, जो पिछले साल की तुलना में 12.8% ज्यादा हैं।

इसी तरह बैंक के औसत CASA (करेंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट) डिपॉजिट्स भी 10.8% की ग्रोथ के साथ 9.18 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं।

बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो (CAR) 19.7% रहा, जो नियामक जरूरत 11.9% से काफी ज्यादा है। यह बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

नियम: नए निवेशक ओएफएस में हिस्सा नहीं ले सकते, जून में आईपीओ आने की उम्मीद

एनएसई के अनलिस्टेड शेयर 2,075 से गिरकर 1,885 पर आए

नई दिल्ली, एजेंसी

NSE के आईपीओ की खबरों के बीच इसके अनलिस्टेड शेयर 2,075 के हाई से गिरकर 1,885 पर आ गए हैं। इसकी वजह SEBI का वह नियम है जिसके तहत केवल वही निवेशक IPO में शेयर बेच सकते हैं जिन्होंने कम से कम एक साल पहले से शेयर होल्ड किए हों।

NSE का शेयर होल्डर बेस एक साल में तेजी से बढ़ा है। 2025 की शुरुआत में जहां 39,000 निवेशक थे, वहीं साल के अंत तक यह बढ़कर 1.8 लाख के पार पहुंच गए।

इतने बड़े और बिखरे हुए बेस के कारण OFS की प्रक्रिया जटिल हो गई है। एक्सचेंज ने इस पूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए बैंकर्स और कानूनी सलाहकारों की एक बड़ी टीम नियुक्त की है।

OFS: कंपनी के प्रमोटर या पुराने निवेशक अपनी हिस्सेदारी आम जनता को बेचते हैं। इससे मिलने वाला पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि शेयर बेचने वाले निवेशकों के पास जाता है।

एनएसई अपने आईपीओ के जरिए 20,000 करोड़ से ज्यादा जुटाना चाहती है। यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा यानी एनएसई खुद कोई नया पैसा नहीं जुटाएगी। सारी रकम मौजूदा शेयरधारकों को मिलेगी जो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। एनएसई करीब 4 से 4.5% इक्विटी इस रास्ते से बेचेगी। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जून तक दाखिल होने की उम्मीद है।

नए निवेशक ओएफएस में शामिल नहीं हो पाएंगे

SEBI के मुताबिक OFS में शेयर बेचने के लिए निवेशक को ड्राफ्ट पेपर दाखिल होने से कम से कम एक साल पहले से शेयर होल्ड करने होंगे। यानी जून 2025 से पहले के खरीदार ही हिस्सा ले सकते हैं। जो निवेशक आज अनलिस्टेड मार्केट से शेयर खरीदेंगे, वे IPO में शेयर नहीं बेच पाएंगे। शेयरधारकों को OFS में शामिल होने के लिए 27 अप्रैल तक अपनी सहमति भी देनी होगी।

निवेशकों के लिए क्या है रिस्क?

शेयरधारकों के लिए सबसे बड़ी अनिश्चितता कीमत को लेकर है, क्योंकि फाइनल प्राइस बुक-बिल्डिंग प्रोसेस से ही तय होगा। इसके अलावा, यदि ऑफर किए गए शेयर पूरी तरह नहीं बिकते हैं, तो बचे हुए शेयरों पर लिस्टिंग के बाद 6 महीने का लॉक-इन पीरियड लागू हो सकता है।

अनलिस्टेड मार्केट: यहां उन कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री होती है जो NSE या BSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं। इसमें निवेशक कंपनी के IPO आने से पहले ही उसके शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन यहां जोखिम और उतार-चढ़ाव ज्यादा होता है।

कनेक्शन कटने से पहले आएंगे 5 मैसेज, लखनऊ समेत प्रदेशभर में स्मार्ट मीटर पर लगी रोक

बैलेंस खत्म होने पर 3 दिन तक नहीं कटेगी बिजली

राहत

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। बिजली के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत दी गई है। अब बैलेंस खत्म होने के बाद अधिकतम 3 दिन या 200 तक (2 किलोवाट लोड तक) बिजली सप्लाई जारी रहेगी। उपभोक्ताओं को समय रहते जानकारी देने के लिए 5-स्तरीय SMS अलर्ट सिस्टम लागू किया जाएगा।

इसमें बैलेंस 30 फीसदी होने पर पहला, 10 फीसदी पर दूसरा, बैलेंस खत्म होने पर तीसरा, डिस्कनेक्शन से एक दिन पहले चौथा और कनेक्शन कटने के बाद पांचवां मैसेज भेजा जाएगा। रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में किसी भी हालत में बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा, भले ही बैलेंस खत्म हो जाए।

दरअसल, बैलेंस खत्म होते ही स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की बिजली कट जा रही थी। इससे उपभोक्ताओं को काफी परेशानी हो रही थी। इसके विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहा था।

मंत्री ने कहा कि स्मार्ट या प्रीपेड मीटर में जो टेक्निकल खामियां है। इसके बारे में जन प्रतिनिधियों ने भी जानकारी दी है। उसमें आईआईटी कानपुर के दो प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही अन्य विशेषज्ञ हैं। यह रिपोर्ट आने तक पूरी प्रक्रिया पर रोक रहेगी। प्रदेश में 82 लाख मीटर लग चुके हैं।

स्मार्ट मीटर में आ रही समस्याओं के बारे में ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को बताया है।

12 लाख लोगों का कटा कनेक्शन

प्रदेश में 82 लाख मीटर लग चुके हैं। इसमें से 70 लाख लोगों ने पेमेंट किया है। 12 लाख लोगों के कनेक्शन बिल नहीं जमा करने के कारण कटे हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर नई तकनीक है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी। स्मार्ट मीटर लगने पर एक महीने तक अगर बैलेंस निगेटिव में जाता है तो भी कनेक्शन न काटे जाएं।

> शक्ति भवन में रविवार को ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है। जिन घरों में स्मार्ट मीटर हाल ही में लगाए गए हैं, वहां करीब 15 दिन की कन्वर्जन टाइम और उसके बाद 30 दिन, यानी कुल 45 दिन तक बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

भीषण गर्मी की शुरुआत, पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

बिना जरूरत घर से बाहर न निकलने की सलाह, पानी और ओआरएस साथ रखें

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । लखनऊ में भीषण गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। इस सीजन में अब तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान भी अपने अधिकतम स्तर 24 डिग्री दर्ज हुआ। इससे रात में खूब गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी रविवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार हो जाएगा। सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। पछुआ हवा भी 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इससे पारा अभी और बढ़ेगा। दिन में तेज धूप के साथ हवा चलती रहेगी। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बिना जरूरी काम के घर के बाहर न निकलें। अपने साथ पानी और ORS लेकर चलें।

मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया जाएगा। दिन के साथ में रात का पारा भी सामान्य से अधिक रहेगा। कल अधिकतम आर्द्रता 50 फीसदी और न्यूनतम 16 फीसदी दर्ज हुई थी। आर्द्रता घटने से मौसम लू चलने की ओर जा रहा है।

लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक तापमान में अभी और बढ़त की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुष्क पछुआ हवा का असर बढ़ने और महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रति चक्रवात के असर से पारा में बढ़त की संभावना बनी हुई है।

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हवाओं की दिशा बदलेगी और आसमान में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। इससे बढ़ते तापमान पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। फिलहाल, बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, केवल गर्मी के तेवर थोड़े नरम पड़ सकते हैं।

मौसम विभाग के ताजा दीर्घकालिक पूर्वानुमान के मुताबिक, साल 2026 में उत्तर प्रदेश में मानसून सामान्य से कमजोर रह सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार कई वैश्विक मौसम कारक बारिश को प्रभावित कर सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी गोलार्द्ध और यूरेशिया में सर्दियों और बसंत के दौरान बर्फ का फैलाव सामान्य से थोड़ा कम रहा है।

लखनऊ में मांझे से बुजुर्ग का गला कटा

लखनऊ। लखनऊ के हैदरगंज-बाजार खाला मार्ग पर रविवार को चाइनीज मांझे से बुजुर्ग का गला कट गया। गनीमत रही कि हेलमेट की बेल्ट होने से बड़ा हादसा टल गया। उनकी पहचान हरिशंकर यादव (62) के रूप में हुई है। वह पारा के रहने वाले हैं। ऐशबाग में अपनी बहन से मिलने आए थे। वह प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। हरिशंकर ने बताया कि वह दोपहर के समय बाइक से जा रहे थे, तभी अचानक उनकी गर्दन पर तेज दर्द महसूस हुआ। कुछ समझ पाते उससे पहले ही मांझे ने गले को काट दिया।

अगर उन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता तो जान भी जा सकती थी। हेलमेट की बेल्ट ने मांझे को पूरी तरह गले तक पहुंचने से रोका और बड़ा हादसा टल गया। कांच लेपित चाइनीज मांझे पर साल 2017 से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद शहर में इसकी बिक्री और इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। यह मांझा न सिर्फ इंसानों बल्कि पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है।

लगातार हो रही घटनाओं के बाद एक बार फिर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि

‘लोकसभा में बिल का गिरना लोकतंत्र की जीत’

अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। अखिलेश यादव ने परिसीमन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में बिल का पास न होना भाजपा सरकार की “बदनीयती की हार” है और यह लोकतंत्र की जीत का प्रतीक है। उनका कहना था कि सरकार जनता की वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही, बल्कि विपक्ष ही लोगों की आवाज बनकर सामने आ रहा है। सपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति का आधार समाज में दरार पैदा करना है।

उन्होंने कहा कि लोगों को बांटकर अविश्वास फैलाना भाजपा की रणनीति रही है, लेकिन अब यह तरीका ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सपा प्रमुख ने भाजपा पर “CMF (Create, Mistrust and Fear)” यानी भ्रम, अविश्वास और भय फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह फार्मूला अब पूरी तरह से विफल हो चुका है और जनता इसे समझ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने फतेहपुर के चाय विक्रेता आर्यन यादव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने दुकान को मनमाने तरीके से सील किया और दुकानदार के साथ मारपीट की गई। अखिलेश यादव ने आर्यन को तांबे के बर्तनों का सेट भेंट करते हुए मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की।

महिला आरक्षण पर सपा का रुख साफ

अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसे जल्दबाजी में लाने का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि बिना जातीय जनगणना के महिला आरक्षण का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पाएगा। उनके मुताबिक, “जब गिनती ही सही नहीं होगी, तो आरक्षण का लाभ कैसे सही तरीके से मिलेगा?” उन्होंने मांग की कि पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए।

परिसीमन बिल पर सियासी संग्राम

- महिला आरक्षण पर सपा का समर्थन, लेकिन जातीय जनगणना के बिना बताया अधूरा
- भाजपा पर समाज में दरार डालने का आरोप

महिलाओं के मुद्दों पर सरकार घिरी

अखिलेश यादव ने कहा कि आज महिलाएं स्वास्थ्य और शिक्षा में भ्रष्टाचार से परेशान हैं और उन्हें सम्मानजनक माहौल नहीं मिल रहा। उन्होंने भाजपा पर महिलाओं के प्रति “पुरानी सामंती सोच” रखने का आरोप लगाया और कहा कि यह सोच उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित करती है।

पसमांदा मुस्लिम समाज 2027 की तैयारी में जुटा

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ । लखनऊ प्रेस क्लब में पसमांदा मुस्लिम महज ने बैठक की। इस बैठक में प्रदेश भर से संगठन से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यों ने प्रेसवार्ता की। इसमें संगठन के अध्यक्ष मुख्तार अंसारी, उपाध्यक्ष वसीम राईन मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में पसमांदा मुसलमानों के अधिकारों को लेकर लंबी चर्चा हुई। वसीम राईन ने कहा कि जो भी पसमांदा समाज को हिस्सेदारी देगा उसे समर्थन किया जाएगा। उपाध्यक्ष वसीम ने कहा कि हम लगातार लोकसभा विधानसभा में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। पूरे भारत में पसमांदा मुस्लिम की बड़ी आबादी है। फिर भी हमारे लोगों को आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। समाज की स्थिति बेहद दयनीय है। विकास से कोसों दूर है, आर्थिक रूप से और शिक्षा के मैदान में हर तरीके से पसमांदा है। योजनाबद्ध तरीके से समाज को शिक्षा और विकास से दूर रखा गया। बहुत सारे लोगों ने जानबूझकर पसमांदा समाज को राजनीति से और विकास से दूर रखा।

- उपाध्यक्ष वसीम बोले- सपा और कांग्रेस ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया

वसीम बोले चुनाव के समय वोट मांगने सब आते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। सभी सियासी पार्टियों ने हमें पीछे रखा। सपा , कांग्रेस, बसपा सबने बेवकूफ बनाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा कोशिश किया कि पसमांदा को हक मिले। प्रदेश और स्थानीय लीडरशिप ने इसे पूरा नहीं होने दिया।

‘रमेश जैन पत्रकार योद्धा ही नहीं मित्रों के मित्र भी थे’

समाज को जोड़ने वाली धार्मिक शख्सियत थे रमेश जैन : शुभचिंतक

तमसा संकेत, संवाददाता

बड़ौत (बागपत)। यू पी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री रहे जुझारू पत्रकार स्वर्गीय रमेश चंद्र जैन को उनके शुभचिंतकों ने केवल पत्रकार ही नहीं समाज को जोड़ने वाला धार्मिक शख्सियत भी बताया। कहा कि रमेश जैन पत्रकार योद्धा ही नहीं मित्रों के मित्र भी थे। कार्यक्रम में ही महाराष्ट्र के जैन मुनि गणधर आचार्य कुंडू महाराज ने फोन पर परिवार को इस दुख को सहन करने एवं परिवार को अपना आशीर्वाद भी दिया। कौशल भवन, बड़ौत में हुई श्रद्धांजलि सभा में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री के पी मालिक, प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे साहब सिंह, बीजेपी नगर अध्यक्ष नीरज शर्मा, जैन समाज के प्रधान मुकेश कुमार जैन, भीम सेन जैन, प्रवीण कुमार जैन, अनिल कुमार जैन, धर्मेंद्र जैन, सुधीर मान, रमेश तोमर प्रधान, अमित शर्मा एडवोकेट, योगेश जिंदल उद्यमी, गौरव, वैभव आशु, आशीष, श्रीमती आरजू, डॉली, सपना जैन, रिद्धि, मुस्कान एवं आरना जैन आदि ने रमेश चंद्र जैन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। कहा गया कि जैन समाज एवं उसकी इकाई में पदाधिकारी चुन कर रमेश चंद्र जैन ने समाज के शिक्षण संस्था एवं मंदिर में भी अपना काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी स्वर्गीय पत्नी ने भी अपने जीवनकाल में बड़ौत के जैन मंदिर में सोने की मूर्ति भेट की थी।

पटेल प्रतिमा पर गूंजी हजारों की आवाज-कड़े कानून की उठी मांग

‘लव जिहाद’ के खिलाफ महापंचायत का महाजुटान

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के व्यस्ततम और प्रतिष्ठित क्षेत्र हजरतगंज स्थित पटेल प्रतिमा पर आज एक अभूतपूर्व जनसमूह देखने को मिला, जब हिन्दू बेटी बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में “एक युद्ध – लव जिहाद के विरुद्ध” महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति ने इसे एक बड़े सामाजिक आयोजन का रूप दे दिया। चारों ओर जागरूकता के संदेश, बैनर और शांतिपूर्ण नारों के बीच यह कार्यक्रम अनुशासन और संयम के साथ संपन्न हुआ।

कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही लोगों का आना शुरू हो गया था। धीरे-धीरे यह संख्या हजारों में बदल गई, जिसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। यह महापंचायत केवल एक विरोध या प्रदर्शन नहीं, बल्कि सामाजिक चिंतन और जागरूकता का मंच बनकर उभरी, जहां लोगों ने एकजुट होकर अपनी बात रखी। मोर्चा द्वारा कार्यक्रम संयोजक अनुराग शुक्ला जी के नेतृत्व में अपनी मांगों से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया।

इस दौरान महापंचायत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की प्रमुख मांग रखी गई, जिससे इस प्रकार के मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, सख्त और प्रभावी कानून लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

- महापंचायत के दौरान अन्य प्रमुख वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे।
- विजय बहादुर सिंह ने कहा कि समाज को इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए एकजुट रहना होगा, तभी सकारात्मक परिवर्तन संभव है।

समाज की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता

महापंचायत के प्रांत कार्यक्रम संयोजक अनुराग शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया कि ऐसे मामलों में सकारात्मक और प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि समाज में विश्वास और सुरक्षा का वातावरण मजबूत हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में ठोस और व्यवस्थित नीति बनाना अत्यंत आवश्यक है।

दिया गया। अनुराग शुक्ला ने सुझाव दिया कि विवाह जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों में माता-पिता की सहमति को भी एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए, जिससे सामाजिक संतुलन और पारिवारिक संरचना को मजबूती मिल सके। कार्यक्रम की एक विशेषता यह रही कि इसमें विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सहित विभिन्न वर्गों के लोगों ने मंच साझा करते हुए सामाजिक एकता और समरसता का संदेश दिया।

पृष्ठ 01 का शेष...

टीएमसी ने बंगाल की बहनों...

बिक्रम ने बताया- मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मेरी दुकान में आकर झालमुड़ी खाएंगे। मैंने उनके लिए झालमुड़ी बनाई। मैंने पैसे लेने से मना किया उन्होंने जबरदस्ती पकड़ा दिए। खा कर बोले कि अच्छा बना है। पीएम ने पढ़ाई के बारे में पूछा मैंने बताया कि गरीबी के चलते ज्यादा नहीं पढ़ सका। फिर पीएम ने कमाई के बारे में पूछा- मैंने कहा कि 1000-1200 रुपए कमा लेता हूं। वे करीब 10 मिनट तक दुकान में रुके, उन्होंने राजनीति की कोई बात नहीं की। पीएम मोदी बोले मैं यहां के किसान और नौजवानों की पीड़ा समझता हूं। मेरा कहना है कि जब तक मंडियों में टीएमसी का सिंडिकेट रहेगा, तब तक शोषण होता रहेगा। आप बीजेपी सरकार लाइए हम टीएमसी की परमानेंट सर्जरी करेंगे।

TMC की सरकार बंगाल टाइगर की दहाड़ से डर गई है। यह बंगाल टाइगर यहां की जनता है। मैं टीएमसी के लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूं अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर दो। क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। बंगाल के चुनाव नया इतिहास बनाने वाला है। टीएमसी का भयकाल जाने वाला है और बीजेपी का सेवाकाल आने वाला है। 4 मई के नतीजे क्या होंगे इसका असर अभी से ही टीएमसी के नेताओं की भाषा में दिख रहा है।

वर्धा और राजनांदगांव में...

दरअसल इन राज्यों में लगातार तीसरे दिन पारा 40C से ज्यादा है।

झारखंड के रांची में चिड़ियाघर के जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर लगाए गए हैं। ओडिशा के 9 जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश भी का अलर्ट है। वहीं दक्षिणी राज्य कर्नाटक के कुछ हिस्सों में ओले गिरने का अलर्ट है।

जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में रविवार को बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

बांदीपोरा जिले की गुरेज घाटी और गांदरबल के सोनमर्ग में बर्फबारी हुई। बर्फ गिरने के कारण मुगल रोड, श्रीनगर-कारगिल रोड और बांदीपोरा-गुरेज रोड समेत कई सड़कें बंद कर दी गई हैं।

कमर में इंजेक्शन पैर सुन्न...

उल्टा, परिवार को कथित तौर पर धमकाया गया— “जो करना है कर लो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।” लगातार बिगड़ती हालत के बीच 07 जनवरी 2026 को युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि घटना के करीब 11 महीने और एफआईआर दर्ज हुए 8 महीने बीत जाने के बावजूद आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को दो बार हिरासत में लेने के बाद भी छोड़ दिया। इससे यह सवाल उठ रहा है कि कहीं न कहीं स्तर पर ढिलाई या दबाव तो नहीं है। मामले को और गंभीर बनाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय से संबंधित फाइल का गायब होना। परिजनों के अनुसार दबाव बढ़ने पर ईमेल के जरिए नई फाइल तैयार की गई, लेकिन मूल फाइल का अब तक कोई पता नहीं चल सका है। इससे साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका और गहरा गई है।

200 फीट गहरी खाई में...

कुछ घायलों को सीढ़ियों के जरिए ऊपर सड़क पर लेकर आए। वहीं कुछ घायलों को कंधों पर उठाकर लाए। सभी यात्रियों को पहले पुष्कर के सरकारी अस्पताल लेकर गए। वहां से उन्हें अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट के बाद पुष्कर घाटी में लंबा जाम लग गया।

लोगों की मदद से 33 यात्रियों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इनमें से पूजा (28) पत्नी विजय सिंह गुर्जर और विमला देवी (50) पत्नी ओम प्रकाश गुर्जर की मौत हो गई। दोनों अजमेर की रहने वाली थीं। वहीं एक घायल को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई। ड्राइवर की तलाश की जा रही है।

पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया- प्रथम दृष्टया मामला ब्रेक फेल होने का लग रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। इस हादसे के दौरान पुष्कर से दाह संस्कार कर अजमेर लौट रहे बोराज गांव के लोगों ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। ग्रामीण घाटी में नीचे उतरे और घायलों को बाहर निकालने में जुट गए।

कुछ घायलों को सीढ़ियों के जरिए ऊपर सड़क पर लाया गया। कई को घाटी के निचले हिस्से से कंधों पर उठाकर लाया गया।

वहीं, सिविल डिफेंस और पुलिस को मौके पर बस यात्रियों का जरूरी सामान भी मिला, जिसे सुरक्षित रूप से पुष्कर थाने में जमा करवाया गया है।

पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया- मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हादसे के अन्य कारणों की जांच की जा रही है।

प्रथम दृष्टया मामला ब्रेक फेल होने का लग रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बस हादसे पर दुख जताया है।

बस में सवार लोग पीसांगन के पास बडसूरी में हरलाल पढ़ियार के यहां मायरा लेकर जा रहे थे। सभी लोग अजमेर के बस स्टैंड के पास के रहने वाले हैं। इनमें अंकुश, शिवराज और राजू गुर्जर का परिवार है। रिश्तेदार और कांग्रेस नेता नौरत गुर्जर ने बताया- मृतकों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। बस का परमिट वैलिड है या नहीं, प्रशासन को इसकी जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए।

तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री...

हादसे के समय फैक्ट्री में 30 मजदूर काम कर रहे थे। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनमें तीन महिलाएं हैं, जो करीब 60 प्रतिशत तक झुलस गई हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। दमकल और रेस्क्यू टीमें कई घंटों से आग बुझाने और मलबा हटाने में जुटी हैं। धमाके के बाद भी पटाखे फूटते रहे, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आई।

शुरुआती जांच में सामने आया कि विस्फोट फैक्ट्री के सामने वाले हिस्से में हुआ है, जहां मजदूर कच्चे सामान के साथ काम कर रहे थे।

तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने X पर लिखा- मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मंत्रियों को तुरंत घटनास्थल पर जाने के लिए कहा है। साथ ही जिला कलेक्टर से बात कर सभी जरूरी सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए।

‘अमेरिका पर भरोसा नहीं’...

दोनों के बीच मतभेद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज स्ट्रेट के नियंत्रण को लेकर हैं।

पजशकियन ने दोहराया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है। सिर्फ आत्मरक्षा में कदम उठा रहा है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर नागरिक ढांचे को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इससे पहले ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बाघेर ने कहा था कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालात कभी भी बिगड़ सकते है। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जाएंगे या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। न्यूज एजेंसी AP ने व्हाइट हाउस के हवाले से बताया कि जेडी वेंस इस वार्ता में शामिल होंगे। वहीं अल जजीरा के मुताबिक ट्रम्प ने इंटरव्यू के दौरान बताया कि सुरक्षा चिंताओं के चलते वेंस इस्लामाबाद नहीं जाएंगे।

‘जैसे आत्मा वैसे सनातन...

ये है भारत के सनातन की आस्था, जो लगातार जारी है। ये भारत का गौरव है। इस गौरव का अहसास करने के लिए ये एक हजार श्रद्धालु उत्तर प्रदेश से सोमनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। इनको यहां प्रस्थान कराने में सुख की अनुभूति हो रही है, क्योंकि जब ये दर्शन करेंगे तो इनके पुण्य के भागीदार हम सब भी होंगे। यह ट्रेन प्रदेशभर से 1008 चयनित श्रद्धालुओं को यात्रा कराएगी।

ट्रेन शाम 4:30 बजे गोमती नगर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। 21 अप्रैल सुबह 6:00 बजे सोमनाथ स्टेशन पहुंचेगी। 24 अप्रैल को वहां से वापसी के लिए ट्रेन रवाना होगी और 26 अप्रैल को लखनऊ पहुंचेगी। आदित्यनाथ ने कहा आज से 10-11 साल पहले कोई सोचता था कि अयोध्या में राम के मंदिर का निर्माण हो पायेगा। आज हर भारतवासी देश ही नहीं, दुनिया में कहीं भी जाए। हर ओर एक ही आवाज उठेगी जय श्रीराम। कोई भी हमें देखता है चाहे वह भारत में हो या दुनिया में, हमें देखते ही अनुमान लगा लेता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। उसकी तरफ से आवाज उठती है जय श्री राम। सोमनाथ यात्रा विशेष ट्रेन के रवाना होने से पहले बटुकों ने मंगलाचरण किया।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ- 226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676